

## संपादकीय

शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके लक्ष्य व्यक्ति, समाज और देश की बुनियादी ज़रूरतों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। अतः इस प्रक्रिया में बदलाव आना स्वाभाविक है। भारत विविधताओं और विषमताओं का देश है पर सभी को समान रूप से शिक्षा मिलना संवैधानिक अधिकार है। समय-समय पर राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, कब पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए। आज हम पुनः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने जा रहे हैं। परंतु क्या हमारी शिक्षा प्रणाली सभी को पढ़ने व बढ़ने के समान अवसर मुहैया करा पा रही है? क्या इससे समाज के सभी वर्ग समान रूप से लाभान्वित हो रहे हैं? मानवीय, सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यों को यह कितना सुदृढ़ कर पा रही है? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में भारी बदलाव की ज़रूरत है आदि ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विभिन्न माध्यमों में गहन चर्चा होती रहती है और हमारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किए जाते हैं।

भारतीय आधुनिक शिक्षा के इस अंक में शिक्षा संबंधी ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सरोकारों से जुड़े लेख शामिल किए गए हैं। संदीप ने अपने लेख में शिक्षा के संवैधानिक अधिकार और नीतिगत प्रावधानों पर

विश्लेषणात्मक टिप्पणी की है और बताया है कि ये प्रावधान वर्तमान संदर्भ में कहाँ तक हर भारतीय बच्चे को समग्रतामूलक गुणवत्ता की शिक्षा देने में कामयाब हैं।

विपिन कुमार शर्मा ने भूमंडलीकरण के संदर्भ में उच्च शिक्षा की चुनौतियों का खुलासा किया है जिनसे हमारा युवा वर्ग जूझ रहा है। लेखक ने वर्तमान उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव की सिफ़ारिश की है।

लगभग तीस वर्षों के बाद हम एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने जा रहे हैं। शिक्षा के विभिन्न हित धारकों – बच्चे, माता-पिता, शिक्षक समुदाय आदि की नई शिक्षा नीति से अपेक्षाएँ होना स्वाभाविक है। भावी शिक्षा नीति से शिक्षक वर्ग को क्या अपेक्षाएँ हैं, विगत शिक्षा नीतियों में शिक्षकों की अपेक्षाओं को किस प्रकार संज्ञान में लिया गया, आदि मुद्दों पर चर्चा की गई है केवलानंद कांडपाल के लेख में।

यदि हम स्वतंत्रता के बाद का इतिहास देखें तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में अनेक बदलाव देखने को मिलेंगे। आज से दस वर्ष बाद शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, विद्यालय व कक्षा कैसे होंगे, बच्चों की क्या अपेक्षाएँ, आवश्यकताएँ होंगी? शिक्षक को किन तैयारियों की आवश्यकता होगी? शिक्षक को

किन तैयारियों की ज़रूरत होगी? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर खोजने की कोशिश की है शशि प्रभा ने अपने लेख में।

वर्तमान समय में परंपरागत भारतीय चिंतन और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समायोजन की आवश्यकता की विवेचना की गई है आरती सिंह के लेख में।

आज शैक्षिक प्रयोग के केंद्र में बालक है, परंतु पूरी शिक्षा व्यवस्था शिक्षक के कंधों पर टिकी हुई है। समय के साथ शिक्षक की भूमिकाओं में बदलाव आया है, परंतु आज भी शिक्षा की ज़िम्मेदारी मूल रूप से शिक्षक पर आ जाती है। उषा शर्मा का लेख यह सोचने का अवसर देता है कि शिक्षक पर आरोप प्रत्यारोप लगाना कहाँ तक उचित है।

इस अंक के कुछ लेख शैक्षिक प्रक्रिया को बाल केंद्रित बनाने तथा कुछ बुनियादी विषयों के रुचिकर शिक्षण से जुड़े हैं।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए पद्मा यादव यह समझा रही हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए और इसे कैसे आयोजित किया जाए। प्राथमिक स्तर पर गिजुभाई की एकल शिक्षा पद्धति का समर्थन किया गया है अस्मा के लेख में। नीरज शर्मा ने कक्षा में कठोर अनुशासन के बजाय आपसी बातचीत और संवाद की सिफ़ारिश की है। सत्यवीर सिंह और अनिल कुमार तेवतिया ने अपने लेख में छोटी-छोटी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में गणित के बुनियादी कौशल विकसित करने पर रोशनी डाली है और संजय रॉय का लेख बेहतर कविता शिक्षण से संबंधित है। अंत में *बचपन से पलायन* नाम की पुस्तक समीक्षा दी गई है, जो पतंजलि मिश्र और भूपेंद्र सिंह द्वारा की गई है। इस अंक को पढ़ने के बाद आप भी सहमत होंगे कि अब शिक्षण पर बात करने के बजाय कुछ करके दिखाने की ज़रूरत है।

*अकादमिक संपादकीय समिति*